## ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल

# कैंसर मरीज़ों के साथ-साथ डॉक्टरों की भी हालत खराब

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** एनएच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते करीब एक साल यानी जब से डॉक्टर नोवक गुप्ता नियुक्त हुये हैं उन कैंसर मरीज़ों का इलाज भी शुरू हो गया, जिन्हें पहले निजी व्यापारिक अस्पतालों को रैफ़र किया जाता था। उसमें न केवल ईएसआई कार्पोरेशन को मोटे भुगतान करने पड़ते थे बल्कि निजी अस्पताल वाले, मरीज़ों को भी डरा-धमका कर उनसे भी अच्छा-खासा ठगते थे।

यह तो अच्छी बात है कि ईएसआई के अपने अस्पताल में इन मरीज़ो का इलाज शुरू हो गया। परन्तु बुरी बात यह है कि दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठे 'बाबू' लोग अपनी जनविरोधी आदतों के चलते यहां न तो आवश्यकतानुसार स्टाफ़ दे रहे हैं और न ही दवायें। एक वर्ष पूर्व जब डॉक्टर नोवक गुप्ता बतौर एंकॉलॉजिस्ट नियुक्त हुये थे ; काम की अधिकता होने के चलते उन्हें शाम 5-6 बजे तक मरीज़ देखने पड़ते थे जबकि 4 बजे अस्पताल की छुट्टी हो जाती है। वे 4 बजे छुट्टी करना भी चाहते तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सुबह से अपनी बारी के इन्तज़ार में बैठे मरीज़ों को बिना देखे छोड़ जाना अमानवीय कहा जाता।

लेकिन उस अमानवीयता के लिये कोई भी मरीज़ ईएसआई निगम मुख्यालय में बैठे निकम्मे बाबुओं को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वे इस कुव्यवस्था से परिचित नहीं होते, उन्हें तो केवल वह डॉक्टर ही दोषी लगता है जो सुबह से बैठा मरीज़ों को देख रहा है।

जानकर बताते हैं कि स्थिति से तंग हो कर जब डॉक्टर नोवक गुप्ता ने नौकरी छोड़ने की तैयारी कर ली तो कहीं जाकर 25 जनवरी को एक विशेषज्ञ डॉक्टर (एंकॉलॉजिस्ट) अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया। इन दोनों डॉक्टरों के पास 250 से अधिक मरीज़ हैं। इन्हें निश्चित समय के अंतराल पर बुला कर दवा (थेरेपी) आदि देकर अगली किसी तारीख पर आने की कह कर भेजा जाता है। इतने मरीज़ों को ट्रीट करना इन दो डॉक्टरों के बस का भी नहीं है। इसके लिये कम से कम चार साधारण डॉक्टर चाहिये जो विशेषज्ञ डॉक्टरों के दिशा निर्देशन पर अमल करते हुए थैरेपी दे सकें। सूत्र बताते हैं कि पूरे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ काम करने के लिये 18 साधारण डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं जो सभी रिक्त पड़े हैं। इतना ही नहीं नर्सिंग स्टाफ़ की कमी के चलते इन डॉक्टरों की हालत और भी खराब होती जा रही है। कैंसर के इलाज में लगने वाली दवायें बहुत महंगी होती हैं। जिनकी आपूर्ति जरूरत के हिसाब से की जाती है यानी स्टॉक में बहुत अधिक मात्रा में नहीं रखी जाती।

लेकिन कई बार देखने में आता है कि डॉक्टर द्वारा लिखे जाने के बावजूद समय पर दवायें मंगाने में कोताही बरती जाती है। सम्बन्धित बाबुओं का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार इतनी महंगी दवायें खरीदने से बचा जाये। यह मरीज़ों के जीवन से तो खिलवाड़ है ही सम्बन्धित डॉक्टरों की पेशेवर छवि के लिये भी घातक है। ऐसे बुरे हालात में भला कोई विशेषज्ञ (एंकॉलॉजिस्ट) डॉक्टर क्यों टिके रहना चाहेगा ?

### ठेकेदार ने आईसीयू वार्ड का कब्ज़ा छोड़ा

सुधी पाठकों ने गतांक में पढा था कि ईएसआई निगम ने अपने एनएच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 बेड का आईसीयू वार्ड ठेके पर दे रखा था जिसे ठेकेदार ने करीब दो साल पूर्व ताला लगा कर बंद कर दिया था।

अब पता चला है कि खबर छपने के तीन दिन बाद ही ठेकेदार ने आनन-फ़ानन में वह वार्ड खाली कर दिया है। खाली भी इतनी जल्दबाज़ी में किया कि उसे अपना सारा सामान उठा कर अस्पताल की बेसमेंट में रखना पड़ा, जहां से वह सामान आठ-दस दिन में उठा कर ले जायेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ईएसआई कार्पोरेशन ने अपने इस वार्ड को खाली कराने के लिये ठेकेदार पर कभी कोई दबाव डाला ही नहीं था। लगता है कि अधिकारीगण इस कब्ज़े की आड़ में अपना नया आईसीयू विकसित करने से बचे रहना चाहते थे।

30 बेड के इस वार्ड के अलावा अस्पताल में कम से कम 70 बेड की ऐसी और भी जगह है जिसमें आईसीयू स्थापित किया जा सकता है। लेकिन ईएसआई कार्पोरेशन को कम से कम साढे तीन सौ नर्सिंग स्टाफ़ व 30 डॉक्टरों अतिरिक्त आवश्यकता होगी। आईसीयू में लगने वाली उपकरणों व अतिरिक्त आवयश्क स्टाफ़ पर होने वाले खर्च को बचाने के चक्कर में मात्र 20 बेड का दिखावटी आईसीयू चलाये रखना चाहता है।

# ठेकेदारों एवं कम्पनियों ने निकाली श्रमिकों की भविष्य निधि राशि

**म. मो. ( फरीदाबाद )** – भविष्य निधि विभाग में कवर्ड ठेकेदारों एवं कम्पनियों ने भविष्य निधि विभाग से लाखों श्रमिकों की पी एफ की राशि को फर्जी तरीके से निकलवाकर हडफने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये राशि उन श्रमिकों की बताई जा रही है जिन्होंने वर्ष 2011 से 2016 के बीच में इन ठेकेदारों व कम्पनियों में काम किया था और अपनी पी एफ की राशि निकलवाई नही थी। अकेले फरीदाबाद रीजन में ही 623 ठेकेदा'व कंपनियों ने लगभग ग्यारह करोड़ रुपये एक ही बैंक खाते में कई कई श्रमिकों कापी एफ निकलवा लिया है तथा अब पी एफ विभाग ऐसे ठेकेदारों एवं कम्पनियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के आलावा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुका है जिसके बाद अनेक ठेकेदारों व कम्पनियों ने काफी राशि वापिस ब्याज सहित जमा भी करवा दी है। विभाग की इस कार्रवाई से ठेकेदारों व कम्पनियों में हडकंप मचा हुआ है।

इस निकासी का पता पी एफ विभाग की अपनी आंतरिक ऑडिट टीम द्वारा ही लगाया गया था जिसके बाद कम्पुटर सॉफ्टवेर द्वारा सभी बैंक खातों की जाँच की गई जिसमे पाया गया कि एक ही बैंक खाते में कई कई श्रमिकों का पी एफ निकलवाया गया है। इसके बाद पी एफ विभाग ने बैंकों से ऐसे बैंक खातों की के वाई सी का विवरण मंगाया जिसमे पाया गया की ठेकेदारों एवं अनेक कम्पनियों ने एक ही बैंक खाते में कई कई श्रमिकों की पी एफ की राशि मंगवा कर खुद निकलवा ली। यह पी एफ की राशि उन श्रमिकों की बताई जा रही है जिन्होंने कभी इन ठेकेदारों एवं कम्पनियों में काम किया था और उन्हें पता ही नही था कि उनका पी एफ भी काटा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मामले बताये जा रहे हैं जिनमे दावेदार तो वास्तविक है लेकिन बैंक का खाता उसके किसी मित्र का है ऐसे मामलों में बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 से पहले बैंक में खाता खुलवाना कठिन था इसलिए श्रमिक आपसी सहमति से एक दूसरे श्रमिक का बैंक खाता दे दिया करते थे और बाद में पी एफ के भुगतान के बाद अपना पी एफ एक दूसरे से ले लेते थे।

वर्ष 2014 से पूर्व के ऐसे मामले भी हैं जब रिटर्न्स ऑनलाइन व आधार पर आधारित नही होती थी , ठेकेदार , ईंट भट्टा मालिक आदि छोटे व्यवसायी अपनी मासिक व वार्षिक रिटर्न्स में वास्तविक कामगारों के नामों की जगह अपने परिवार वालों के नाम डाल दिया करते थे और बाद में उस पी एफ की राशि को अपने किसी खाते में निकलवा लेते थे। पाठकों को बताते चले कि पी एफ विभाग उन सभी ठेकेदारों एवं कम्पनियों से नमूना हस्ताक्षर मंगवाकर रखता है जिन्हें वे पी एफ दावों का भुगतान करने हेतु दावा प्रपत्रों को सत्यापित करने को अधिकृत करते हैं। पिछले वर्ष तक पी एफ निकासी के सभी दावे फिजिकल रूप में आते थे जो अब लगभग ऑनलाइन आने लगे हैं जिनमे श्रमिक का पूरा विवरण नियोक्ता द्वारा पहले ही अपने डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया होता है। फिजिकल दावों में पी एफ का पैसा मंगाने हेतु बैंक का खाता व उसका पता हाथ से लिखा जाता था जिसके आधार पर ही यह सारा खेल खेला गया है।

**गौरतलब है कि 751 सदस्यीय यूरोपीय संसद में 562 सदस्यों ने सीएए को भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी बताते हुए प्रस्ताव पेश किए हैं और भारत सरकार से भेदभावपूर्ण संशोधन को रद्द करने को कहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर एतराज जताते हुए कहा है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है और संसदीय प्रक्रिया निभाते हुए कानून बनाया है, जबकि मोदी सरकार ने पिछले वर्ष यूरोपीय संसद के अपने समर्थक सदस्यों के कश्मीर की निजी यात्रा पर आमंत्रित किया था। इससे मोदी सरकार की नीति में विरोधाभास झलकता है।**

**सीएए, एनआरसी व एनपीआर के विरोधियों को बदनाम करने, डराने, धमकी व चुनौती देने, देशद्रोही कहने व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भाषा बोलने का आरोप लगाने तथा समाज में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बजाए मोदी सरकार को चाहिये कि देश में सुख-शांति बहाल करने व आपस में सौहार्द स्थापित करने के लिये सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर खुले मन से विचार-विमर्श का संवाद स्थापित करके विवाद का हल निकाले।**

**गतांक की चीर-फ़ाड़**

## मोदी सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों से चिकित्सा के नाम पर आयुष्मान भारत का देशव्यापी ढिंढोरा

**डॉ. जुगल किशोर गुप्ता**

**मज़दूर मोर्चा के 26 जनवरी-1 फ़रवरी 2020** के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार के नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ़ देश व्यापी धरने- प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में इन कानून के विरुद्ध धरना प्रदर्शन पिछले डेढ माह से चल रहा है, जिसमें सभी धर्म , जाति व वर्ग के युवा, बूढे बच्चे व औरतें भाग ले रहे हैं। शहीन बाग की तर्ज पर देश के अनेक नगरों में भी धरना देने की रिपोर्ट आ रही हैं। इन धरना-प्रदर्शनों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विदेश के अनेक नगरों में भी इन कानूनों के विरोध में धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि कुछ नगरों में समर्थन में भी प्रदर्शन हुए हैं।

इस धार्मिक व सामाजिक एकता से बौखलाकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) तथा मोदी सरकार ने सीएए, एनपीआर व एनआरसी के प्रति जन समर्थन जुटाने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शनों-धरनों को बदनाम करने व समाप्त करने की मुहिम चला रखी है। सरकार से असहमति जताने वालों पर देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाए जा रहे है तथा सभाओं व रैली में भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश (यूपी) में सीएए के खिलाफ़ धरना-प्रदर्शनकारियों पर सत्ता के इशारे पर हिंसा भड़काने के झूठे आरोप लगाकर पुलिस का दमन चक्र चलाया जा रहा है।

रिहाई मंच के अध्यक्ष वकील मुहम्मद शुऐब जिन्होंने सीएए के खिलाफ़ आवाज़ उठाने पर एक महीने जेल में यातनाएं भुगती थी ने 'सीएए के खिलाफ़ हो रहे प्रदर्शनों में योगी के इशारे पर हिंसा फैल रही है यूपी पुलिस' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस द्वारा की जा रही प्रताड़ना का पर्दाफ़ाश किया है। खुले रूप से पुलिस के अधिकारी मुसलमानों, गरीबों और वंचितों को हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं।

आरएसएस व भाजपा ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच व अल्पसंख्यक मोर्चा गठित कर मुसलमानों को सदस्य बनाया था। इन मुस्लिम सदस्यों ने बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में भाजपा की सराहना की तथा ट्रिपल तलाक कानून का विरोध नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार द्वारा सीएए-एनआरसी जैसे कानून बनाने और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने के प्रयास से मुसलमानों का सरकार से भरोसा उठ गया है। फलस्वरूप भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम सदस्यों ने नाराज होकर इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है, जिसका 'सीएए-एनआरसी से नाराज भाजपा के 76 मुस्लिम सदस्यों ने दिया इस्तीफ़ा, बोले हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पर हम कब तक फंसे रहेंगे?' में खुलासा किया गया है।

**कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद ज्यादातर इलाकों में पांच महीनों से इंटरनेट व ब्रॉडबैंड बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ब्रॉडबैंड पूरी तरह से शुरू नहीं किये गए हैं और न ही इंटरनेट बंद करने के आदेश की समीक्षा की गई है, जिसका 'कश्मीर:नेटबंदी इस तरह जन्नत को बदल रही है दोजख में' विश्लेषण किया गया है। इंटरनेट पर प्रतिबंध लगने से वहां शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार आदि पर बुरा प्रभाव पड़ा है और कश्मीर की आंतरिक अर्थव्यवस्था की रीढ पूरी तरह टूट चुकी है।**

प्रधानमंत्री मोदी अक्सर भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की बात करते हैं, जबकि उनकी सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने एम्स में लूट व भ्रष्टाचार के आरोपी वहां तैनात अपने चहेते हिमाचल प्रदेश काडर के एक आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को बचाने के लिये एम्स के तत्कालीन मुख्य विजिलेंस अधिकारी व हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को एम्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसका 'भाजपा के नये अध्यक्ष नड्डा भी अमितशाह से कम नहीं' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है। अब उन्हीं नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार पनपने का और आसार नज़र आते हैं। स्मरण रहे कि भाजपा के पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए पकड़े गये थे।

जब केन्द्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से भाजपाई नेता और कार्यकर्ता देश के कानूनों की कोई परवाह नहीं करते। वे अपने भाषणों में अक्सर ज़हर उगलते नज़र आते हैं, हिंदू राष्ट्र का शिगूफ़ा छोड़ देते हैं, महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं और यदि पुलिस इनके विरुद्ध कोई कार्यवाई करती है तो वे पुलिस के साथ आक्रामक हो जाते हैं। 'जे पी नड्डा के स्वागत समारोह में महिला सिपाही से अश्लील हरकत करते पकड़ा गया भाजपा कार्यकर्ता' में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा महिला सिपाही से अश्लील हरकत करने व अन्य भाजपाइयों द्वारा पुलिस से दबंगई करने का भांडा-फ़ोड़ किया गया है।

मोदी सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों से चिकित्सा के नाम पर आयुष्मान भारत का देशव्यापी ढिंढोरा पीटा जा रहा है जबकि मज़दूरों के वेतन से हर माह साढे छ: प्रतिशत की वसूली करने से ईएसआई निगम के खजाने में जमा कई लाख-करोड़ रुपये की राशि को मज़दूरों को वांछित चिकित्सा सुविधाएं देने के लिये खर्च नहीं किया जा रहा, जबकि इसमें मोदी सरकार के पल्ले से कुछ नहीं जाता। फलस्वरूप फ़रीदाबाद स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में अकसर डॉक्टरों, स्टाफ़, उपकरणों आदि की भारी कमी रहती है, जिसका खामियाजा मज़दूरों को भुगतना पड़ता है। 'मोदी सरकार का ईएसआई निगम कर रहा मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़' में इस अस्पताल की बदहाली की परतें खोली गई है।

सीएए, एनआरसी व एनपीआर के विरोधियों को संघ परिवार व मोदी सरकार द्वारा धमकाने, डराने, चेतावनी देने तथा देशद्रोही करार देने और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की मुहिम पर कविता 'सत्ता' में तथा एआरसी में नागरिकता के लिये काग़जात के मांगे जाने पर कविता 'हमार पास काग़ज नैना' में उचित व्यंग्य किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नौकरियों के बारे में चर्चा न करने पर 'परीक्षा पर चर्चा-इस मंच पर भी कभी आइए साहब...नौकरी पर चर्चा' व 'जो परीक्षाएं दे चुके हैं उनके साथ नौकरी पे चर्चा भी होनी चाहिए' तथा पब्लिक सेक्टर कंपनियों में विनिवेश करने का अभियान चलाने पर 'मैं अपनी कार के पहिये बेच दूंगा, गियर बॉक्स बेच दूंगा, स्टेरिंग, बैटरी और टायर-टयूब भी बेच दूंगा, पर सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं कार नहीं बिकने दूंगा' कार्टूनों द्वारा उपयुक्त तंज कसा गया है।

**फ़रीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण निगम जनता से पैसे वसूल करने के बावजूद बदले में अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा और जनता को जो नागरिक सेवाएं मिलनी चाहिए उनके प्रति लापरवाह है, जिसका 'फ़रीदाबाद नगर निगम कर चोरों पर तो कार्यवाही लेकिन कामचोरों और रिश्वतखोरों को छूट' तथा 'नगर निगम में भरा 1.65 करोड़ का जुर्माना, दोषी अफ़सरों की सेहत पर असर नहीं' में समीक्षा की गई है। सोचने वाली बात है कि निगम जिसकी आर्थिक दशा पहले ही बदहाल रहती है वह खजाने से 1. 65 करोड़ का जुर्माना पर्यावरण बोर्ड में भुगतान करने के बाद और संकट में आ जायेगी। लेकिन विभाग के तेज तर्रार मंत्री अनिल विज को निगम की बदहाली की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है।**